नवोन्मेष
रुक्टा (राष्ट्रीय)

राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)
(अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से संबद्ध)

website: www.ructarashtriya.org **Email:** info@ructarashtriya.org, ructarashtriya@gmail.com

केन्द्रीय कार्यालय : देराश्री शिक्षक सदन, राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर, जयपुर-302004
प्रधान कार्यालय : सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, अजमेर-305001 (राज.)
अध्यक्ष : डॉ. दिग्विजयसिंह शेखावत, बीकानेर मो. 9414452369, 9983007575
महामंत्री : डॉ. नारायणलाल गुप्ता, अजमेर मो. 9414497042

परिपत्र क्रं. : रुक्टा (रा.)/2015-16/04 पौष कृष्ण १२ वि. स. २०७२ तदनुसार 07 जनवरी, 2016
(सभी इकाई सचिवों एवं सक्रिय सदस्यों को समस्त सदस्यों में प्रसारित करने के अनुरोध सहित प्रेषित)

प्रिय महोदय/महोदया,

सादर नमस्कार।

पिछले परिपत्र के पश्चात् श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय, सीकर में सम्पन्न संगठन के 54वें प्रान्तीय अधिवेशन के विवरण, महामंत्री प्रतिवेदन, अंकेक्षित आय-व्यय लेखा, साधारण सभा द्वारा पारित प्रस्तावों के साथ यह परिपत्र आपके समक्ष प्रस्तुत है।

54वें प्रांतीय अधिवेशन का विवरण

संगठन का 54 वाँ प्रान्तीय अधिवेशन 31 दिसम्बर 2015 व 1 जनवरी 2016 को श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय, सीकर में सम्पन्न हुआ। अधिवेशन में राज्य के सभी जिलों से राजकीय महाविद्यालयों, निजी महाविद्यालयों एवं छह विश्वविद्यालयों के 1600 से अधिक प्रतिनिधियों ने सहभाग किया। अधिवेशन के संभागियों में महाविद्यालयों के व्याख्याताओं, शारीरिक शिक्षा निदेशकों, पुस्तकालयाध्यक्षों, निदेशालय के सहायक, उप एवं संयुक्त निदेशकों, विश्वविद्यालयों के आचार्यों, सहायक एवं सह आचार्यों सहित अनेक सेवानिवृत्त शिक्षक शामिल थे।

उद्घाटन सत्र एवं देराश्री व्याख्यान - अधिवेशन के प्रथम दिन दीप-प्रज्ज्वलन और मंगलाचरण के बाद इस अधिवेशन के उद्घाटन एवं देराश्री स्मृति व्याख्यानमाला के संयुक्त सत्र में देराश्री स्मृति व्याख्यान मुख्यवक्ता श्री राममाधवजी (राष्ट्रीय महासचिव, भाजपा) द्वारा दिया गया। उन्होंने पं. दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित 'एकात्ममानव दर्शन' की व्याख्या करते हुए कहा कि एकात्ममानव दर्शन एक मुक्त चिंतन है, अन्य वादों की तरह किसी एक दृष्टिकोण में बाँधने वाला नहीं, यह मानवता-केन्द्रित दर्शन है - चिंतन है। उन्होंने बताया कि पं. उपाध्याय ने कहा था कि एकात्ममानव दर्शन में मेरा कुछ भी नहीं है, मैंने तो भारतीय चिन्तकों, महापुरुषों के विचारों का संकलन मात्र किया है अथवा भारत का मूल चिंतन हमारी परम्पराओं में अभी भी रूप-परिवर्तन के साथ विद्यमान है। यह एक ऐसा जीवन-दर्शन है, जो देश, काल, व्यक्ति से परे है। वस्तुतः यह हमारे धर्म तत्त्व के रूप में स्थित है, जो

अपरिवर्तनीय है। उन्होंने कहा कि धर्म को जीवन पद्धति मात्र नहीं कहा जा सकता है, वरन् धर्म हमारे जीवन का दर्शन है, जिसमें सभी के सुख की कामना की जाती है। एकात्म मानव-दर्शन एक ऐसा विचार है, जिसमें सुख सार्वजनिक, सार्वदेशिक, सार्वकालिक और सार्वभौमिक होता है। उन्होंने कहा कि एकात्म मानव दर्शन एक ईश्वर, कई ईश्वर से आगे जाकर सभी ईश्वर है, इस भाव को प्रतिपादित करता है। चराचर जगत में एक ही सत्य का प्रकटीकरण भिन्न-भिन्न रूप में है, अत: सृष्टि में संघर्ष नहीं वरन् समन्वय यह प्राकृतिक अवस्था है। उन्होंने उपस्थित शिक्षक साथियों से इस विषय पर गहन शोध कर व्यक्ति से लेकर समष्टि के हित में वैचारिक आंदोलन खड़ा करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के मुख्य-अतिथि श्री कालीचरणजी सराफ (उच्च-शिक्षा मंत्री, राज.) ने कहा - हम शिक्षकों की प्रत्येक समस्या को दूर करने के लिए कृत-संकल्प हैं, महाविद्यालय शिक्षकों के पदनाम परिवर्तन शीघ्र किये जायेंगे। महाविद्यालय शिक्षकों की डी.पी.सी., सी.ए.एस. का लाभ, आर.वी.आर.ई.एस. के सी.ए.एस. लाभ, पीएच.डी. में कोर्स वर्क की छूट आदि कार्य यथाशीघ्र पूरे किए जायेंगे। अगले सत्र के प्रारम्भ में ही सभी रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह निर्णय भी लिया है कि उपखण्ड स्तर तक के स्थानों पर नए राजकीय महाविद्यालय खोले जाएँ। इससे पूर्व संगठन महामंत्री ने शिक्षकों की सभी प्रमुख समस्याओं को माननीय उच्च शिक्षामंत्री के सामने रखते हुए कहा कि शिक्षकों को विश्वास में लेना आवश्यक है, शिक्षकों की भावनाओं और माँगों का दमन न किया जाए, न ही उन्हें विविध कार्य देकर मशीन बनाया जाए, जब हमारे कार्य आपके माध्यम से स्वीकृत होकर आगे क्रियान्वयन के लिए चले जाते हैं, फिर भी रुक क्यों जाते हैं, हमें उस रुकावट के कारण को जानकर उसका निदान करना होगा। ब्यूरोक्रेसी पॉलिसी मेकर न बनें। संगठन अध्यक्ष डॉ. दिग्विजयसिंह ने कहा कि यह संगठन मात्र शिक्षक-हित की बात नहीं करता है, अपितु यह शिक्षण-व्यवस्था और नवाचारों के प्रयोग के प्रति भी पूर्ण समर्पित है। यहाँ विचार और संगठन का सहभाव हमारी परम्पराओं, कर्त्तव्यों आदि के क्रियान्वयन में ही निहित है। स्थानीय सांसद एवं कार्यक्रम अध्यक्ष श्री सुमेधानंदजी सरस्वती ने कहा कि जहाँ शिक्षक जागरुक होता है, वह देश आगे बढ़ता है। शिक्षा-क्षेत्र में आज भी संसाधनों की कमी है, मैं उन्हें दूर करने का शिक्षा मंत्री से आग्रह करता हूँ। इसके बाद सभी अतिथियों ने 54वें अधिवेशन के अवसर पर संगठन द्वारा प्रकाशित बाबा साहेब अम्बेडकर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आधारित स्मारिका **''संगच्छध्वम्''** का विमोचन भी किया। मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रो. जगदीशप्रसादजी सिंघल, कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर और अधिवेशन संयोजक डॉ. जी. एस. कलवाणिया का. प्राचार्य, श्री कल्याण महाविद्यालय भी मौजूद रहे।

खुला सत्र एवं साधारण सभा - सायंकाल खुला सत्र एवं साधारण सभा का आयोजन किया गया। इस सत्र में शिक्षक प्रतिनिधियों द्वारा शिक्षक समस्याओं का प्रस्तुतिकरण किया गया। महामंत्री ने वर्ष भर में संगठन द्वारा शिक्षक समस्याओं के समाधान में हुई उपलब्धियों एवं गतिविधियों तथा सम्पन्न सांगठनिक-वैचारिक कार्यक्रमों का ब्यौरा-महामंत्री प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। जिसे सदन द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। इसके पश्चात् प्रांतीय अंकेक्षक डॉ. सोमकांत भोजक ने 31 मार्च 2015 को सम्पन्न वित्तीय वर्ष का आय-व्यय लेखा एवं चिट्ठा सदन के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे साधारण सभा द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। इसके अतिरिक्त साधारण सभा द्वारा तीन प्रस्ताव सर्वसम्मति

से स्वीकृत किये गए - 1. समाज में सर्वविध समरसता निर्माण हेतु सामूहिक प्रयास किए जाएँ। 2. राज्य की उच्च शिक्षा एवं शिक्षकों की समस्याओं का समाधान अविलंब किया जाये। 3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति समग्र चिंतन पर आधारित हो। साधारण सभा द्वारा गत अधिवेशन के पश्चात् दिवंगत शिक्षक साथियों को दो मिनट मौन रख कर श्रद्धांजलि भी दी गई।

सेवानिवृत्त शिक्षक साथियों का सम्मान एवं सांस्कृतिक संध्या - खुले सत्र के पश्चात् सीकर विभाग में निवास कर रहे 63 सेवानिवृत्त शिक्षक साथियों का सम्मान प्रो. जगदीश प्रसादजी सिंघल, कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, प्रो. संतोषजी पाण्डेय सम्पादक शैक्षिक मंथन एवं प्रो. धर्मचन्दजी जैन, पूर्व अध्यक्ष रुक्टा (रा.) द्वारा शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिह्न भेंट कर किया गया। इसके पश्चात् आयोजित सांस्कृतिक संध्या में स्थानीय कलाकारों ने देश भक्ति एवं भक्ति रस से सराबोर नाट्य एवं संगीतमय प्रस्तुतियाँ देकर उपस्थित शिक्षकों को भाव विभोर कर दिया।

शैक्षिक संगोष्ठी - अधिवेशन के द्वितीय दिवस 1 जनवरी 2016 को आयोजित शैक्षिक संगोष्ठी में दो महत्त्वपूर्ण व्याख्यान हुए - 1. सामाजिक समरसता और 2. विकास की भारतीय अवधारणा। सामाजिक समरसता पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तर पश्चिम क्षेत्र प्रचारक श्री दुर्गादासजी ने कहा कि भारतीय जन-मानस में सदैव समरसता का भाव और उसके प्रति जागरूकता रही है। उन्होंने राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में ऐतिहासिक उदाहरणों के दृष्टान्त रखते हुए बताया कि यहाँ के महापुरुषों ने ही नहीं, राजाओं में से भी बहुतों ने समरसता के भाव को समाज में महत्त्व दिया था। आज भी मूल धारा में यही भाव है, किन्तु जागरुकता का अभाव हो गया है, हमें पुनः जागरुक होकर अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करना होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तर क्षेत्र संघचालक एवं अ.भा. कार्यकारिणी सदस्य मा. डॉ. बजरंग लाल जी गुप्त ने विकास की भारतीय अवधारणा को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए कहा कि इसमें आवश्यकताओं के अनुसार न्यूनतम प्रकृति का दोहन किया जाता रहा है यहाँ का व्यक्ति सर्वहित और सर्वसुख की कामना करता है। यहाँ सम्पत्ति पर स्वयं का स्वामित्व नहीं माना गया। भारतीय अवधारणा में सबके लिए उपभोग की व्यवस्था जैसे मन्दिरों में भोग लगाने के बाद उसे प्रसाद मानकर सब में वितरण की व्यवस्था, त्याग और समर्पण की अनूठी मिसाल है। अतः यहाँ की विकास की अवधारणा में न्यूनतम दोहन और अधिकतम वितरण की व्यवस्था रही है, पूरे विश्व को इस ओर आना होगा, उन्होंने जीडीपी के वर्तमान मापन को गलत बताते हुए सुमंगलम विकास का सुझाव दिया। उन्होंने सुमंगलम विकास की व्याख्या करते हुए सबको रोटी, सबको स्वास्थ्य, सबको शिक्षा व सबको रोजगार देने की बात कही। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए एमडीएस विश्वविद्यालय अजमेर के कुलपति प्रो. कैलाश सोडाणी ने कहा कि वर्तमान समय में समाज में सामाजिक-समरसता का भाव जागृत करने का कार्य शिक्षक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश में वेद-वन्दना के साथ-साथ राष्ट्र-वन्दना भी होनी चाहिए। इस सत्र का संयोजन डॉ. राजेन्द्र शर्मा ने किया। संगोष्ठी में डॉ. श्यामलाल, डॉ. पी.डी. राजोरा, डॉ. ओमप्रकाश पारीक, डॉ. गीताराम शर्मा एवं डॉ. प्रमोदकुमार शाह द्वारा शोध पत्र प्रस्तुत किये गये।

समारोप कार्यक्रम - अधिवेशन के समारोप सत्र के मुख्य-अतिथि राजस्थान सरकार के शिक्षा-मंत्री प्रो. वासुदेवजी देवनानी ने अपने उद्‌बोधन में कहा कि हमें अपनी शिक्षा पद्धति और पाठ्यक्रम को भारत के अनुकूल बनाना होगा, हमारे पाठ्यक्रम में जीवन-मूल्य परक शिक्षा का समावेश करना होगा।

हम पाठ्यक्रम में हमारे महापुरुषों का जीवन-चरित्र डालें, जिससे बालक उनके आदर्शों को जीवन में उतार सके, हमारे लिए चन्द्रगुप्त, अशोक, चाणक्य, महाराणा प्रताप, शिवाजी, वीर सावरकर, सुभाषचन्द्र बोस आदि महान् नायक है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के लिए रुक्टा (राष्ट्रीय) भारतीय आदर्शों के अनुसार कार्य कर रहा है, मैं इसका सदस्य हूँ यह कहते हुए मुझे भी गर्व होता है। अध्यक्षीय उद्‌बोधन में प्रो. जगदीशप्रसादजी सिंघल कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने कहा कि रुक्टा (राष्ट्रीय) मात्र शिक्षक-समस्याओं के लिए ही संघर्ष नहीं करता, अपितु हम वैचारिक अधिष्ठान पर कार्य करते हैं, हम शैक्षिक नवाचारों को जीवन में कैसे उतारें और वे कौन-कौन से हो सकते हैं, इस पर भी व्यापक चिन्तन करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि वह हमारे शिक्षकों को उचित सुविधाएं भी दें। कार्यक्रम के अन्त में आयोजक इकाई के सचिव डॉ. अरविन्द महला एवं संगठन महामंत्री ने धन्यवाद ज्ञापित किया। राष्ट्रगान के साथ अधिवेशन सम्पन्न हुआ। अधिवेशन में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के संगठन मंत्री श्री महेन्द्रजी कपूर, रा. स्व. संघ के उत्तर पश्चिम क्षेत्र कार्यवाह श्री हनुमान सिंहजी एवं क्षेत्र प्रचारक श्री दुर्गादासजी पूरे समय उपस्थित रहे।

शुभकामना संदेश - 54वें प्रांतीय अधिवेशन की सफलता एवं इस अवसर पर प्रकाशित स्मारिका "**संगच्छध्वम्**" हेतु सरसंघचालकजी मा. मोहनरावजी भागवत, मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजेजी, उच्च शिक्षा मंत्री श्री कालीचरणजी सराफ, एवं अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के संरक्षक प्रो. के.नरहरिजी के शुभकामना संदेश प्राप्त हुए। संगठन सभी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता है।

संगठन ने शिक्षक समस्याओं के लिए निरन्तर संघर्ष करते हुए व्यापक शिक्षा एवं समाजहित में कार्य करने की छवि बनाई है। शिक्षक समस्याओं पर कार्य करने के साथ-साथ शिक्षक की समाज में प्रतिष्ठा भी बने, इस अनुरूप संगठन के कार्यक्रमों की रचना रहती है। ऐसा ही एक वैचारिक कार्यक्रम कर्तव्य बोध दिवस हम गत कुछ वर्षों से प्रति वर्ष 12 जनवरी से 23 जनवरी के मध्य सम्पन्न करते आये हैं। इस वर्ष भी इकाईश: आयोजित कर्तव्य बोध कार्यक्रमों में आपकी सक्रिय सहभागिता का अनुरोध है।

साभार

भवदीय

(डॉ. नारायणलाल गुप्ता)
[महामंत्री]

20, चित्रकूट कॉलोनी,
माकड़वाली रोड़, अजमेर-305004

अमृत वचन

"प्रत्येक कर्तव्य पावन है और कर्तव्यनिष्ठा ईश्वरोपासना का सर्वोत्तम प्रकार है। जो कर्तव्य हमारे बिल्कुल समीप है, जो कर्तव्य हमारे हाथों में है उसे अच्छी प्रकार करके हम स्वयं को ही बलवान करते हैं और इस प्रकार एक-एक पग पर अपनी शक्ति को बढ़ाते हुए हम उस अवस्था में पहुँच जायेंगे जब हमें जीवन तथा समाज में सबसे जटिल और सम्मानित कर्तव्यों के पालन करने का सुअवसर भी प्राप्त होगा।"

- स्वामी विवेकानंद

राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)
54वाँ प्रांतीय अधिवेशन, श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय, सीकर

दिनांक 31 जनवरी 2015 व 1 जनवरी 2016

महामंत्री प्रतिवेदन

संगठन का 53 वाँ प्रदेश अधिवेशन 18 व 19 फरवरी 2015 को श्री गोविन्द गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा में सम्पन्न हुआ। 53वें अधिवेशन एवं उसके पश्चात् शिक्षक समस्याओं के समाधान हेतु संगठन द्वारा किए गए प्रयासों एवं उपलब्धियों के साथ सम्पन्न सांगठनिक एवं वैचारिक कार्यक्रमों का विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत है-

शिक्षक समस्याओं के संबंध में उपलब्धियाँ एवं गतिविधियाँ

* **30 जून 2013 तक पात्र शिक्षकों के पे-बैंड-4 के आदेश जारी** - गत वर्ष नवम्बर माह में आयोजित वरिष्ठ व चयनित वेतनमान की स्क्रीनिंग के समय से ही संगठन ने अनेक बार उच्च शिक्षा मंत्रीजी एवं विभाग के अधिकारियों से भेंट कर एवं पत्र लिख कर 30 जून 2010 तक चयनित वेतनमान में पदोन्नत महाविद्यालय शिक्षकों को बिना ए.पी.आई. अंक व किसी संवीक्षा प्रक्रिया के पे-बैंड-4 का लाभ प्राचार्य स्तर पर स्वीकृत करने की लगातार माँग की। संगठन के लगातार प्रयासों व दबाव की सकारात्मक परिणिति के रूप में 30 जून 2010 तक चयनित वेतनमान में पदोन्नत महाविद्यालय शिक्षकों को उनके द्वारा चयनित वेतनमान में 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर बिना किसी ए.पी.आई. अंक की आवश्यकता के प्राचार्य स्तर पर ही पे-बैंड-4 देने के आदेश दिनांक 10-11-2015 को जारी हो गए।
* **वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान स्वीकृति पर 3 प्रतिशत वेतन वृद्धि के आदेश** - राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा दिनांक 12-10-2009 को जारी छठे वेतनमान के आदेशों में सी.ए.एस. के तहत वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान स्वीकृति के समय 3 प्रतिशत की एक वेतनवृद्धि का प्रावधान होने के बावजूद अनेक महाविद्यालयों में शिक्षकों को उक्त लाभ नहीं दिया जा रहा था। संगठन के निरन्तर प्रयासों से इस संदर्भ में दिनांक 22-4-2015 को स्पष्टीकरण आदेश जारी किये गए।
* **वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान की एरियर राशि के नगद भुगतान के आदेश** - गत 10-12-2014 को आयुक्तालय द्वारा 189 शिक्षकों को वरिष्ठ एवं 356 शिक्षकों को चयनित वेतनमान स्वीकृत किए थे। अनेक महाविद्यालयों में एरियर राशि के नगद भुगतान को लेकर संशय होने पर संगठन के प्रयासों से आयुक्तालय द्वारा दिनांक 26 मार्च 2015 को एरियर के नगद भुगतान के आदेश प्रसारित किए गए।
* **परिवीक्षा काल में कार्यरत व्याख्याताओं का मानदेय संशोधित** - मुख्यमंत्रीजी द्वारा राज्य सेवा में परिवीक्षा काल में कार्यरत कर्मचारियों व अधिकारियों के मानदेय में वृद्धि की घोषणा का लाभ महाविद्यालय शिक्षकों पर लागू करने के लिए संगठन द्वारा दबाव बनाया गया। संगठन के प्रयासों के परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा दिनांक 2 जुलाई 2015 को परिवीक्षाकाल में कार्यरत महाविद्यालयों

शिक्षकों, पुस्तकालाध्यक्षों एवं शारीरिक शिक्षकों का नियत मानदेय 1 सितम्बर 2014 से 21840 एवं 1 जुलाई 2015 से 24030 रुपये करने के आदेश प्रसारित किये गए।

* **परीक्षा पारिश्रमिक वृद्धि** - विश्वविद्यालय परीक्षा पारिश्रमिक वृद्धि के लिए संगठन के निरन्तर दबाव की परिणिति में गत सत्र 2014-15 से अनेक विश्वविद्यालयों में परीक्षा संबंधी सभी कार्यों के लिए देय पारिश्रमिक दरों में वृद्धि की गई। कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा पारिश्रमिक नहीं बढ़ाया गया था अथवा वृद्धि समान नहीं थी। इस संदर्भ में संगठन ने राज्यपाल महोदय एवं संबंधित विश्वविद्यालयों के कुलपति से पारिश्रमिक में एकरूपता लाने का आग्रह किया। संगठन के प्रयासों से अधिकांश विश्वविद्यालयों के परीक्षा पारिश्रमिक संशोधित हो चुके हैं। कुछ विश्वविद्यालयों के परीक्षा पारिश्रमिक दरों में विसंगतियों के निवारण की कार्यवाही चल रही है।

* **जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की संवैधानिक कमेटियों में सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए अध्यादेश संशोधन हेतु कमेटी गठित** - जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, जो पूर्व में परिसर विश्वविद्यालय था, को संभागीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने के बाद अन्य विश्वविद्यालयों की भांति सिंडीकेट, सीनेट एवं अन्य कमेटियों में संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों का प्रतिनिधित्व देने हेतु संगठन ने लगातार दबाव बनाया। संगठन के लगातार प्रयासों से जोधपुर विश्वविद्यालय के कुलपति ने सम्बद्ध महाविद्यालय शिक्षकों को वैधानिक समितियों में प्रतिनिधित्व देने के लिए कमेटी का गठन कर दिया है।

* **1-1-2006 से पूर्व सेवानिवृत्त कॉलेज शिक्षकों, पुस्तकालाध्यक्षों एवं शारीरिक शिक्षकों की पेंशन संशोधन** - 1-1-2006 से पूर्व सेवानिवृत्त ऐसे कॉलेज शिक्षकों, पुस्तकालाध्यक्षों एवं शारीरिक शिक्षकों जिन्होंने सेवानिवृत्ति पूर्व चयनित वेतनमान में 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली थी उनका पेंशन नियतन पे-बैंड 4 व ए. जी.पी. 9000 के अनुसार करने की माँग संगठन राज्य सरकार से लगातार करता आया है। राज्य सरकार द्वारा प्रकरण में सकारात्मक रूख नहीं रखने के कारण सेवानिवृत्त शिक्षक साथियों को माननीय उच्चतम न्यायालय में इस मामले को ले जाना पड़ा। अन्ततः उच्चतम न्यायालय द्वारा न्याय प्रदान करते हुए प्रार्थी शिक्षकों की पेंशन संशोधित करने का निर्णय दिया गया है। संगठन ने पुनः राज्य सरकार से अपील की है कि इस संबंध में प्रार्थी शिक्षकों के समान ही पात्र सभी सेवानिवृत्त शिक्षकों की पेंशन को भी संशोधित किया जाय।

* **महाविद्यालयों में सेवानिवृत्त व्याख्याताओं एवं कार्मिकों की सेवाएँ संविदा पर प्रारम्भ** - प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक व प्रशासनिक कार्यों को निर्बाध रूप से संचालित करने के लिए लोक सेवा आयोग से नियमित चयन होने तक संगठन ने रिक्त पदों को अस्थाई तौर पर सेवानिवृत्त व्याख्याताओं एवं कार्मिकों से भरने की माँग की थी। संगठन की माँग के अनुरूप आयुक्तालय ने सेवानिवृत्त व्याख्याताओं एवं कार्मिकों को रिक्त पदों पर संविदा पर रखने की प्रक्रिया प्रारम्भ की। इसी श्रृंखला में आयुक्तालय ने आवेदनों के आधार पर 64 सेवानिवृत्त व्याख्याताओं, 32 मंत्रालयिक कर्मचारियों, 27 प्रयोगशाला सहायकों एवं 13 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संविदा पर नियुक्ति के आदेश प्रसारित कर दिए।

❋ **व्याख्याताओं के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु कार्यवाही** - प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए संगठन के निरन्तर प्रयासों के कारण राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 1070 पदों की भर्ती हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। इन पदों की अभ्यर्थना भेजने के बाद राजकीय महाविद्यालयों में सेवानिवृत्ति एवं अन्य कारणों से कई और पद रिक्त हो गए थे। संगठन द्वारा सरकार के ध्यान में यह विषय लाया गया एवं इन रिक्त पदों पर भी भर्ती की माँग की गई। संगठन की माँग के अनुसार राज्य सरकार द्वारा सत्र 2014-15 तक खाली हुए अन्य 220 पदों पर भर्ती हेतु लोक सेवा आयोग को अभ्यर्थना भेजी जा चुकी है एवं लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है।

❋ **मंत्रायलिक कर्मचारियों की भर्ती हेतु कार्यवाही** - प्रदेश के महाविद्यालयों में मंत्रायलिक कर्मचारियों की कमी के चलते महाविद्यालयों में प्रशासनिक एवं सामान्य काम-काज पर विपरीत प्रभाव पड़ता रहा है। संगठन लगातार इस विषय को पत्रों द्वारा तथा व्यक्तिगत भेंटवार्ताओं में उठाता रहा है। संगठन के इन निरन्तर प्रयासों के कारण महाविद्यालय शिक्षा के लिए लिपिक ग्रेड II (कनिष्ठ लिपिक) के 192 पदों की अभ्यर्थना राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रायलिक सेवा चयन बोर्ड को भिजवाई गई है। शीघ्र ही इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ होने की संभावना है।

❋ **प्राचार्य/उपाचार्य पद की डी.पी.सी. कार्यवाही प्रारम्भ** - संगठन लगातार प्रयासरत रहा है कि शिक्षकों को पदोन्नति लाभ समय पर प्राप्त हो एवं जिन महाविद्यालयों में प्राचार्य/उपाचार्य पद रिक्त है, उन महाविद्यालयों के सुचारू संचालन हेतु शीघ्र प्राचार्यों/उपाचार्यों की नियुक्ति की जाए। इस संबंध में संगठन ने प्राचार्य/उपाचार्य पद की डी.पी.सी. शीघ्र करवाने की माँग लगातार पत्रों एवं भेंटवार्ताओं में की थी। संगठन के दबाव के चलते उच्च शिक्षा विभाग ने आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है, संगठन को आशा है कि शीघ्र ही प्राचार्य/उपाचार्य पद पर डी.पी.सी. पूर्ण कर रिक्त पदों पर पदस्थापन कर दिया जाएगा।

❋ **प्राचार्य सम्मेलन में प्रमुख शासन सचिव (उच्च शिक्षा) द्वारा किए गए दुर्व्यवहार की निंदा** - 3 अगस्त 2015 को जयपुर में राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों के सम्मेलन में प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा श्री पवन कुमार गोयल ने प्राचार्यों पर बेबुनियाद आरोप लगाते हुए उनके साथ दुर्व्यवहार किया। संगठन के संज्ञान में आते ही 4 अगस्त 2015 को उच्च शिक्षा मंत्रीजी को पत्र लिख कर एवं 7 अगस्त को व्यक्तिशः मिलकर प्राचार्य सम्मेलन में श्री गोयल के निरकुंश एवं गैर जिम्मेदाराना व्यवहार की निंदा की गई तथा शिक्षकों की भावनाओं को उनके समक्ष रखते हुए श्री गोयल को भविष्य में संयत व्यवहार रखने के निर्देश देने का आग्रह किया। उच्च शिक्षा मंत्रीजी ने पूरे प्रकरण को गंभीरता से सुनकर इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने एवं भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न होने के निर्देश दिये।

❋ **भेंट वार्ताएँ** - शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के तीव्र एवं न्यायोचित समाधान करवाने हेतु संगठन ने समय-समय पर राज्यपाल महोदय, उच्च शिक्षा मंत्रीजी एवं विभाग के अधिकारियों से भेंट की।

❑ **राज्यपाल महोदय से भेंट** - संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने 11 मई एवं 6 अक्टूबर को राज्यपाल

महोदय से भेंट कर पदनाम परिवर्तन में वित्त विभाग द्वारा लगाई गई आपत्तियों के निस्तारण एवं विश्वविद्यालयों से संबंधित विभिन्न समस्याओं के निराकरण का आग्रह किया। संगठन द्वारा यू.जी.सी. रेग्यूलेशन, सूचना के अधिकार में प्राप्त राज्य सरकार द्वारा यू.जी.सी. को भेजी गई जानकारियों, एम.एच.आर.डी. के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों तथा 20 से अधिक राज्य सरकारों द्वारा जारी कॉलेज शिक्षकों के पदनाम परिवर्तन संबंधी आदेशों को संलग्न करते हुए राज्यपाल महोदय के समक्ष 400 से अधिक पृष्ठों का विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत किया। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल महोदय से विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति करवाने की प्रक्रिया प्रारंभ करवाने की माँग भी की। संगठन द्वारा सभी विश्वविद्यालयों में शोध को बढ़ावा देने के लिए संबद्ध महाविद्यालयों में कार्यरत पात्र शिक्षकों को पीएच.डी. सुपरवाईजर बनाने सहित शोध संबधी विभिन्न समस्याओं के निवारण करने, सेवारत महाविद्यालय शिक्षकों को पीएच.डी. हेतु कोर्स वर्क में छूट देने, जोधपुर विश्वविद्यालय की सिंडिकेट व अन्य कमेटियों में संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों को प्रतिनिधित्व देने एवं सभी विश्वविद्यालयों के परीक्षा पारिश्रमिक में एकरूपता लाने का भी आग्रह किया। राज्यपाल महोदय ने संगठन के पक्ष को विस्तार से सुना एवं आवश्यक निर्देश दिए।

❑ **उच्च शिक्षामंत्रीजी से भेंट** - संगठन शिक्षक समस्याओं के निराकरण के लिए उच्च शिक्षामंत्रीजी से लगातार सम्पर्क में रहा। संगठन द्वारा 7 अप्रेल, 11 मई, 7 अगस्त, 6 सितम्बर, 6 अक्टूबर, 25 नवम्बर एवं 19 दिसम्बर 2015 को उच्च शिक्षामंत्रीजी से की गई भेंटों में विभिन्न शिक्षक समस्याओं के शीघ्र समाधान की माँग करते हुए उनके समर्थन में विभिन्न तथ्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये गए। संगठन के दृष्टिकोण से सहमत होते हुए विभिन्न समस्याओं के समाधान के क्रम में मंत्रीजी द्वारा सकारात्मक निर्देश प्रदान किये गए।

संगठन द्वारा की गई भेंटों में पदनाम परिवर्तन करने, पीएच.डी. के दोहरे लाभ प्रकरण में वसूली निरस्त करने एवं पीएच.डी. प्रोत्साहन वेतन वृद्धियाँ प्रारम्भ करने, पूर्व सेवा का लाभ सभी पात्र शिक्षकों को देने, निदेशक पद पर वरिष्ठतम शिक्षक नियुक्त करने, संतोषजनक ए.सी.आर. के आधार पर चयनित वेतनमान देने, आर.वी.आर.ई.एस. शिक्षकों को सी.ए.एस. लाभ देने, सेवारत शिक्षकों को पीएच.डी. कोर्स वर्क से छूट देने अथवा छह माह के सवैतनिक अवकाश की व्यवस्था करने, अन्य राज्य कर्मचारियों की भांति 2-1-2006 से 30-6-2006 के मध्य वार्षिक वेतनवृद्धि वाले शिक्षकों को अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने, संविदा शिक्षकों को यू.जी.सी. द्वारा अनुशंसित न्यूनतम वेतन देने सहित अन्य लंबित समस्याओं को शिक्षक हित में हल करने की माँग की गई। इसके अतिरिक्त बड़े महाविद्यालयों को विखंडित करने के उपरांत अभी तक सुचारू व्यवस्था नहीं किये जाने पर मंत्रीजी का ध्यान दिलाया गया तथा माँग की गई कि विखंडित महाविद्यालयों को शीघ्र स्वंतत्र रूप से चलाने की समुचित व्यवस्थाएँ की जाएँ अथवा इनका पुनः एकीकरण कर दिया जावे। मंत्रीजी ने संगठन को बताया कि इस संबंध में निर्णय ले लिया गया है एवं अन्तिम आदेश हेतु मुख्यमंत्री कार्यालय को फाईल भेज दी गई है। संगठन ने 30 जून 2013 के बाद के वरिष्ठ चयनित वेतनमान एवं पे-बैंड-4 के लिए शीघ्र स्क्रीनिंग

करवाने, आर.वी.आर.ई.एस. में नियुक्त शिक्षकों को उनकी अनुदानित पद पर सेवा अवधि के छठे वेतनमान के एरियर हेतु अनुदान देने, पूर्व संचित उपार्जित अवकाश नकदीकरण हेतु अनुदान उपलब्ध करवाने अथवा व्यापक हित में उपार्जित अवकाश एवं मेडिकल अवकाश को राज्य सेवा में अग्रनीत करने हेतु भी भेंटवार्ताओं में दबाव बनाया है।

❑ **अधिकारियों से भेंट** - पदनाम परिवर्तन से संबंधित 400 से अधिक पृष्ठों का विस्तृत ज्ञापन संयुक्त सचिव (सी.एम.ओ.) को 11 मई को दिया गया। 11 मई एवं 6 सितम्बर को उच्च शिक्षा से जुड़े अधिकारियों के साथ सम्पन्न बैठकों में विभिन्न शिक्षक समस्याओं के निराकरण संबंधी ज्ञापन दिये गये एवं समर्थन में विस्तृत दस्तावेज प्रस्तुत किये।

* **लिखे गये पत्र** - शिक्षकों की सामूहिक एवं व्यक्तिगत समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए संगठन द्वारा लगातार राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा एवं आयुक्त कॉलेज शिक्षा सहित संबंधित अधिकारियों को लगातार विस्तृत पत्र लिख कर समाधान का प्रयास किया गया। कुछ प्रमुख समस्याओं का समाधान हो चुका है कुछ समस्याओं के समाधान के प्रयास चल रहे हैं। इस क्रम में संगठन द्वारा पीएच.डी. के दोहरे लाभ प्रकरण का निस्तारण करने, पूर्व सेवा लाभ सभी पात्र शिक्षकों को देने, निदेशक (अकादमी) पद पर शिक्षक की नियुक्ति करने, संतोषजनक ए.सी.आर. के आधार पर चयनित वेतनमान देने, आर.वी.आर.ई.एस. शिक्षकों को सी.ए.एस. लाभ देने, 30 जून 2013 के बाद के वरिष्ठ चयनित वेतनमान एवं पे-बैंड-4 के लिए शीघ्र स्क्रीनिंग करवाने, आर.वी.आर.ई.एस. में नियुक्त शिक्षकों को उनकी अनुदानित पद पर सेवा अवधि के छठे वेतनमान के एरियर हेतु अनुदान देने, पूर्व संचित उपार्जित अवकाश नकदीकरण हेतु अनुदान उपलब्ध करवाने अथवा उपार्जित अवकाश एवं मेडिकल अवकाश को राज्य सेवा में अग्रनीत करने, परिवीक्षा काल में कार्यरत शिक्षकों को राजकीय सेवा के सम्पूर्ण लाभ देने, सेवारत शिक्षकों को पीएच.डी. कोर्स वर्क से छूट देने, 2-1-2006 से 30-6-2006 के मध्य वार्षिक वेतनवृद्धि वाले शिक्षकों को अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने, संविदा शिक्षकों को यू.जी.सी. द्वारा अनुशंसित न्यूनतम वेतन देने, निजी पालिटेक्निक महाविद्यालयों के परीक्षा केन्द्र राजकीय महाविद्यालयों से हटाने, छात्र संघ चुनाव के दौरान झुंझुंनु महिला महाविद्यालय के शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार करने वाली उपखण्ड अधिकारी पर कार्यवाही करने, भरतपुर के राजकीय महाविद्यालय से अभियान्त्रिकी महाविद्यालयों का परीक्षा केन्द्र हटाने, नवगठित कृषि विश्वविद्यालयों में कुलपति पद नियुक्ति हेतु योग्यता संशोधन करने, आर.पी.एस.सी. द्वारा कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा हेतु शैक्षिक योग्यता पर पुनःविचार करने, 1-4-1994 के बाद नियुक्त शिक्षकों के स्थायी करने के आदेश प्रसारित करने, 1-4-1994 के बाद की वरिष्ठता सूची जारी करने, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें अन्य कर्मचारियों के साथ ही लागू करने, स्वायत्तशासी महाविद्यालय योजना हेतु शिक्षकों व विद्यार्थियों से विचार विमर्श करने, प्रतिनियुक्ति पर लगाये शिक्षकों को नियमानुसार टी.ए., डी.ए. एवं अवकाश स्वीकृत करने, आर.वी.आर.ई.एस. 2010 में राज्य सेवा का विकल्प नहीं देने वाले शिक्षकों के पद पर अनुदान जारी करने आदि विषयों पर राज्यपाल,

मुख्यमंत्रीजी, उच्च शिक्षा मंत्री जी एवं सक्षम अधिकारियों से पत्र व्यवहार किया। संगठन ने माननीय संसाधन विकास मंत्रीजी को पत्र लिख कर आग्रह किया है कि कतिपय कारणों से कुछ शिक्षक समय पर रिफ्रेशर/ऑरियन्टेशन कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले पाए हैं अत: व्यापक हित में रिफ्रेशर/ऑरियन्टेशन कार्यक्रम की छूट 31 दिसम्बर 2015 तक बढ़ाई जाए।

गत सम्मेलन के पश्चात् प्राध्यापकों की समस्याओं के निराकरण हेतु संगठन विभिन्न गतिविधियों, भेंटवार्ताओं, ज्ञापनों एवं पत्राचार के माध्यम से निरन्तर सक्रिय रहा है। संगठन की सक्रियता के परिणामस्वरूप पूर्व में लंबित एवं तात्कालिक रूप से उत्पन्न कई समस्याओं का समाधान भी शिक्षक हित में हुआ है। किन्तु रुक्टा (राष्ट्रीय) कतिपय कुछ समस्याओं के समाधान से संतुष्ट होने वाला नहीं है, संगठन निरन्तर संघर्ष कर बढ़ते जाने के मंत्र पर चलने वाला है। अभी कई प्रमुख समस्याओं का समाधान बाकी है। इनका जब तक शिक्षक हित में समाधान नहीं हो जाता, हम रुकने, थकने या बैठने वाले नहीं है। लोकतंत्रात्मक पद्धति से आप सभी शिक्षक साथियों के सहयोग से शेष सभी समस्याओं के निराकरण हेतु प्रयास जारी हैं।

सांगठनिक एवं वैचारिक गतिविधियाँ

❋ **प्रदेश अधिवेशन** – संगठन का 53 वाँ प्रांतीय अधिवेशन 18 व 19 फरवरी 2015 को गोविन्द गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा में सम्पन्न हुआ। अधिवेशन में राज्य भर के लगभग 1500 शिक्षक साथियों ने हिस्सा लिया। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि अ. भा. रा. शैक्षिक महासंघ के महामंत्री प्रो. जे. पी. सिंघल एवं अध्यक्ष शैक्षिक महासंघ के अध्यक्ष डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल रहे। कार्यक्रम में भारतीय गुरु शिष्य परंपरा पर केन्द्रित स्मारिका ''तेजस्विनावधीतमस्तु'' का भी विमोचन किया गया। देराश्री स्मृति व्याख्यान पेसिफिक विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलपति प्रो. भगवती प्रसाद शर्मा ने दिया। अधिवेशन में समूहश: बैठकों एवं खुले सत्र में विभिन्न शिक्षक समस्याओं पर मंथन किया गया। वार्षिक साधारण सभा में महामंत्री प्रतिवेदन एवं 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के अंकेक्षित आय-व्यय विवरण तथा बेलेंसशीट को सदन ने सर्वसम्मति से अनुमोदित किया। इसके अतिरिक्त साधारण सभा ने पूर्व में पारित प्रस्तावों की पुन: पुष्टि करते हुए दो नवीन प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए (1) शैक्षिक परिसरों के वातावरण को संस्कारक्षम बनाने के लिए सभी पक्षों द्वारा मिलजुल कर प्रयास किये जायें। (2) शोध हेतु सभी प्रकार के प्रोत्साहन एवं सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ। अधिवेशन के द्वितीय सत्र में ''मूल्य परक शिक्षा की प्रासंगिकता'' विषय पर आयोजित शैक्षिक संगोष्ठी के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तर-पश्चिम क्षेत्र कार्यवाह श्री हनुमानसिंह राठौड़ थे। समारोप कार्यक्रम रा. स्व. संघ के अखिल भारतीय सहसम्पर्क प्रमुख प्रो. अनिरुद्ध देशपांडे के मुख्य आतिथ्य एवं म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर के कुलपति प्रो. कैलाश सोढ़ानी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। अधिवेशन में अगले दो वर्ष के लिए नवीन कार्यकारिणी हेतु मनोनीत कार्यकर्ताओं के नामों की घोषणा भी की गई।

* **नवसंवत्सर कार्यक्रम** - केन्द्र के आह्वान पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रुक्टा (राष्ट्रीय) की विभिन्न इकाइयों ने भारतीय नववर्ष विक्रम संवत् २०७२ समारोह पूर्वक मनाया। शिक्षक समुदाय द्वारा व्यक्तिशः मित्रों एवं संबंधियों को बधाई संदेश एवं शुभकामनाएँ प्रेषित की गईं। सामूहिक रूप से महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर में तथा चौराहों पर सभी को तिलक लगाकर एवं प्रसाद वितरित कर शुभकामनाएँ दी गई। इसके अतिरिक्त अजमेर, गंगापुरसिटी, चुरू, सिरोही, नसीराबाद, तारानगर में भारतीय नववर्ष के महत्व एवं भारतीय कालगणना की वैज्ञानिकता पर संगोष्ठियाँ भी आयोजित की गई।
* **अम्बेडकर जयंती पर नमन** - संगठन की विभिन्न इकाईयों द्वारा बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती पर उनके कर्त्तत्व एवं व्यक्तित्व का स्मरण करते हुए उनके द्वारा बताई समरसता की राह पर चलने का संकल्प लिया गया।
* **गुरु वंदन कार्यक्रम** - केन्द्र की योजना के अनुरूप रुक्टा (रा.) की 128 इकाईयों द्वारा प्रदेश भर में गुरु-वंदन कार्यक्रम सम्पन्न किये गये। इस अवसर पर आदिगुरु महर्षि वेदव्यास को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए भारत की गुरु-शिष्य परम्परा, उनके बीच पावन संबंध और वर्तमान में उनकी भूमिका पर प्रेरक व्याख्यान आयोजित किए गए। प्रबुद्ध एवं चिंतनशील शिक्षकों/वक्ताओं द्वारा आदि गुरुओं के प्रेरणास्पद आचरण एवं त्याग के उदाहरणों से प्रेरित होकर बेहतर समाज निर्माण की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता जताई गई।
* **शिक्षक सम्मान निधि** - अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ द्वारा प्रतिवर्ष अद्वितीय एवं अविस्मरणीय योगदान देने वाले शिक्षकों के सम्मान के निमित्त स्थापित अक्षय कोष हेतु संगठन की योजना से प्रदेश के 4400 से अधिक शिक्षक साथियों से रु. 100/- प्रति शिक्षक की सहयोग राशि प्राप्त हुई।
* **विभागीय सम्मेलन** - प्रदेश की योजना के अनुसार सितम्बर-अक्टूबर माह में रुक्टा (राष्ट्रीय) के 10 विभागों अलवर, भरतपुर, जयपुर-प्रथम, जयपुर-द्वितीय, जोधपुर, पाली, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा एवं कोटा विभागों के विभाग सम्मेलन सफलता पूर्वक सम्पन्न हुए। संगठन के अध्यक्ष, महामंत्री, संगठनमंत्री, उपाध्यक्ष, संयुक्त मंत्री, संभाग संगठन मंत्रियों की अलग-अलग विभागीय सम्मेलनों में संगठन के प्रान्तीय प्रतिनिधि के रूप में सहभागिता रही। इन विभागीय सम्मलेनों में प्रान्तीय प्रतिनिधियों द्वारा संगठन की गतिविधियों एवं विभागीय सम्मेलनों के औचित्य बताने सहित वैचारिक विषय रखे गये। सहभागियों द्वारा खुले सत्र में शिक्षक समस्याओं से अवगत कराया गया, उपस्थित प्रान्तीय प्रतिनिधि द्वारा विभिन्न समस्याओं पर संगठन द्वारा की जा रही कार्यवाही से सदन को अवगत कराया गया, शेष रही नवीन समस्याओं की जानकारी प्रतिनिधियों द्वारा केन्द्र तक पहुँचाई गई।
* **राष्ट्रीय अधिवेशन में सहभागिता** - अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का त्रिदिवसीय छठा राष्ट्रीय अधिवेशन 9 से 11 अक्टूबर 2015 तक नागपुर में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन में संगठन के 62 कार्यकर्ताओं ने सक्रिय सहभाग किया।
* **प्रदेश कार्यकारिणी बैठकें सम्पन्न** - 21 मार्च एवं 22 नवम्बर को संगठन की प्रांतीय कार्यकारिणी

तथा 17 जून एवं 16 अगस्त को विस्तृत कार्यकारिणी की बैठक सम्पन्न हुई। इनमें संगठन की विभिन्न गतिविधियों एवं आगामी कार्ययोजना पर गंभीरता से विचार विमर्श कर निर्णय लिए गए।

* **सदस्यता** - पिछले तीन वर्षों से संगठन की सदस्यता सीमित समय में करने की योजना पर कार्य हुआ है। पिछले वर्षों में रहे उत्साहजनक परिणाम के आलोक में इस वर्ष प्रदेश कार्यकारिणी ने संगठन की सदस्यता 1 से 15 जुलाई के मध्य ही एकत्र करने का निर्णय किया। सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से सार्थक परिणाम प्राप्त हुए एवं इस सत्र् हेतु राजकीय महाविद्यालयों से 4209, विश्वविद्यालयों से 204, एवं निजी संस्थाओं से 843 शिक्षकों की कुल **5256** सदस्यता प्राप्त हुई है। जो की गत वर्ष की सदस्यता से 231 अधिक रही। यह उल्लेखनीय है कि नए सत्र के प्रथम दिन अधिकतम सदस्यता दिवस पर सभी कार्यकर्त्ताओं के सक्रिय योगदान से एक ही दिन में रिकार्ड 4241 सदस्यता का संग्रहण हुआ।

* **राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक** - अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 14 जून 2015 को नई दिल्ली में एवं 8 अक्टूबर 2015 को नागपुर में महासंघ अध्यक्ष डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। संगठन की ओर से इन बैठकों में अध्यक्ष, महामंत्री एवं प्रदेश महिला प्रतिनिधि ने सक्रिय सहभाग किया।

* **इकाईयों द्वारा सम्पन्न विशेष कार्यक्रम** - राजकीय महाविद्यालय अजमेर इकाई द्वारा पृथ्वीराज जयंती, महाराणा प्रताप जयंती, अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस, सफाई अभियान एवं वृक्षारोपण के कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद इकाई द्वारा रक्षा बंधन पर्व, राजकीय कन्या महाविद्यालय अलवर इकाई एवं राजकीय महाविद्यालय टोंक इकाई द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न किए गए।

शिक्षक समस्याओं के समाधान हेतु तथा संगठन के कार्य एवं विचार के विस्तार हेतु हुई गतिविधियाँ योजनानुसार सफलता पूर्वक सम्पन्न हो सकी हैं तो इसका सम्पूर्ण श्रेय संगठन के सक्रिय कार्यकर्ताओं और आप सब शिक्षक बंधु, बहिनों को ही है। संगठन के प्रति आप सबके प्रेम, सहयोग एवं विश्वास के कारण ही यह संभव हो पाया है। इन गतिविधियों या समस्या-समाधान की प्रक्रिया में आपकी अपेक्षानुसार जो कार्य नहीं हुआ है तो उसके लिए पूर्णत: स्वयं को उत्तरदायी मानकर आपसे करबद्ध क्षमायाचना करता हूँ तथा आपके निरन्तर सहयोग, मार्गदर्शन एवं विश्वास हेतु हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ।

भवदीय

(डॉ. नारायणलाल गुप्ता)
[महामंत्री]

रुक्टा (राष्ट्रीय) के 54 वें प्रान्तीय अधिवेशन में साधारण सभा द्वारा पारित प्रस्ताव

प्रस्ताव क्रं. 1. समाज में सर्वविध समरसता निर्माण हेतु सामूहिक प्रयास किए जाएँ।

भारतवर्ष इस अखिल भूमण्डल का एक अनोखा देश है। रंग-रूप, भाषा-भूषा, जाति-पंथ, क्षेत्र-प्रान्त आदि का वैविध्यपूर्ण अपार विस्तार किसे आकर्षित नहीं करता। किस भारतीय को गर्व की अनुभूति नहीं होती, जब कनाडा में बैठा पाकिस्तान मूल का एक मुस्लिम-अध्येता व विद्वान् लेखक (तारेक फतह) भारत की इस विविधता की छटा पर मुग्ध होकर पूरे विश्व के समक्ष अपनी पत्नी के हवाले से यह उद्‌गार व्यक्त करता है कि यदि किसी दिन यह दुनिया खत्म हो जाए और एक हिन्दुस्थान बचा रह जाए, तो दुनिया फिर से खड़ी हो जायेगी।

किन्तु यह भी एक कटु सत्य है कि कालान्तर में इसी विविधता के जाति-पंथ आदि कतिपय आयामों के कारण देश और समाज में विभेद की दीवारें खड़ी हो गई। यह तो हमारी गतिशील सांस्कृतिक चेतना का वैशिष्ट्य है कि सामाजिक व्याधियों के जन्म के साथ ही उनके प्रतिकार के लिए कोई तुकाराम, रैदास, कबीर, नानक, दयानंद, विवेकानंद, भीमराव उपस्थित हो जाता है। जिन समाजों में यह सुधारात्मक प्रवृत्ति समानान्तर रूप से नहीं जन्मती, उनके खण्ड-खण्ड बिखरने में अधिक समय नहीं लगता। हमारे यहाँ भी पुनर्जागरण के प्रयत्न न हुए होते तो समाज का विखण्डन निश्चित था।

हम सौभाग्यशाली हैं कि नाना संतों के पुण्य-प्रताप के कारण हमारा पुण्यप्रवाह अविरत है, हमारी सामाजिक चेतना अविच्छिन्न है। परन्तु जब समाज में कुरीतियाँ-रूढ़ियाँ-विषमताएँ-विद्रूपताएँ बद्धमूल हो चुकी होती हैं, तो उनके समूल उन्मूलन में शताब्दियाँ बीत जाती है। आज भी जाति, वर्ग जैसे भेदक तत्व सामाजिक प्रगति के मार्ग में बाधक बने हुए हैं। अस्पृश्यता रूपी विष से जनित मूर्च्छा एक सीमा तक दूर हुई है तथापि उसका एकान्तिक व आत्यन्तिक निवारण नहीं हुआ है। ऊँच-नीच के भाव का अभाव नहीं हुआ है। ''जात-पाँत पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई'' के जाप के बीच भी ''कौन जात हो?'' के स्वर अब भी स्पष्ट सुने जा रहे हैं। इसलिए समाज में अब भी पदे-पदे गर्त-गह्वर-खात हैं, जिन्हें पाटना है।

खाई को पाटने के लिए स्वेदान्त श्रम अपेक्षित होता है। यह श्रम निरन्तर हो भी रहा है; वैयक्तिक और सामूहिक दोनों स्तरों पर। वैयक्तिक स्तर पर आधुनिक काल में इस प्रसंग में सबसे बड़ा पुरुषार्थ डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने किया है। उनका समग्र जीवन ही अस्पृश्यतोन्मूलन-अस्पृश्योन्नति-दलितोद्‌धार के कार्य के लिए समर्पित रहा है। हम बाबा साहेब की 125 वीं जन्म जयंती माना रहे हैं, सो बाबा साहेब के समरस समाज के अपूरित संकल्प की स्मृति व पूर्ति का अवसर भी है और समाज की अपेक्षा भी है। अत: हम यह सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करते हैं कि समरसतामूलक समाज के निर्माण के लिए मनसा वाचा कर्मणा सन्नद्‌ध रहकर अपना योगदान करेंगे। हम शिक्षक होने के नाते समाज में ''ओपिनियन मेकर'' की भूमिका में हैं। हमारा दायित्व है समाज के मार्गदर्शन का, कार्यस्थल पर भी और उसके बाहर भी। कक्षा-कक्ष के माध्यम से भी हम समाज तक पहुँच सकते हैं और सहजता से समाज-जागरण का कार्य सम्पादित कर सकते हैं।

रुक्टा (रा.) अपने शिक्षक सदस्यों, शिक्षाविदों, शिक्षाहितैषी समाज बंधुओं व शिक्षार्थियों से आह्‌वान

करता है कि हम अपनी प्रत्यक्ष-परोक्ष भूमिका का स्वयमेव वरण करें और समाज में सर्वविध समरसता के निर्माण से सहभागी बनें।

प्रस्ताव क्रं. 2. राज्य की उच्च शिक्षा एवं शिक्षकों की समस्याओं का समाधान अविलंब किया जाये।

राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) की साधारण सभा पूर्व में पारित एवं अनिस्तारित समस्त प्रस्तावों की पुन:पुष्टि करते हुए शैक्षिक-उन्नयन एवं शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हेतु सरकार से माँग करती है कि निम्न समस्याओं का शीघ्र सकारात्मक निस्तारण किया जाए -

1. यू.जी.सी. रेग्यूलेशन के अनुसार महाविद्यालय शिक्षकों के पदनाम परिवर्तित करने के आदेश तत्काल प्रसारित किए जायें।
2. महाविद्यालयों में व्याख्याताओं, शारीरिक-शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों और मंत्रालयिक कर्मचारियों के रिक्त पद तुरन्त प्रभाव से भरने की व्यवस्था की जाये।
3. शिक्षा-शिक्षार्थी का अनुपात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदण्डानुसार निर्धारित करते हुए कार्यभार का पुन: निर्धारण किया जाये एवं तदनुसार नवीन पदों का सृजन किया जाये।
4. पूर्व सेवा का लाभ सभी पात्र शिक्षकों को दिया जाए।
5. शोध एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने हेतु शोध-उपाधि प्राप्त शिक्षकों को यू.जी.सी. मानदण्डानुसार प्रोत्साहन स्वरूप देय वेतन वृद्धि पुन: प्रारम्भ की जाये। शिक्षकों को शोध करने हेतु कोर्स-वर्क की अनिवार्यता से छूट प्रदान की जाये अथवा छह माह के सवैतनिक अवकाश की व्यवस्था की जाए।
6. विभागीय पदोन्नति समिति एवं कॅरियर एडवान्समेन्ट स्कीम के तहत वरिष्ठ, चयनित एवं पे-बैंड-4 के परिलाभों हेतु वर्ष में दो बार नियमित बैठकें आयोजित हों। 30 जून, 2013 के बाद सी.ए.एस. लाभ हेतु पात्र शिक्षकों की संवीक्षा बैठक अविलम्ब आयोजित की जाये।
7. परिवीक्षाधीन अवधि में कार्यरत महाविद्यालय शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि को नियमित सेवा मानते हुए वेतन सहित समस्त परिलाभ प्रदान किये जायें।
8. आर.वी.आर.ई.एस. सेवा के तहत कार्यरत शिक्षकों को कॅरियर एडवान्समेंट का लाभ तथा छठे वेतन आयोग की बकाया राशि का भुगतान शीघ्र करवाया जाये। इन शिक्षकों के चिकित्सा अवकाश एवं उपार्जित अवकाश राज्य सेवा में अग्रनीत किये जायें।
9. संविदा आधार पर नियुक्त शिक्षकों को यू.जी.सी. द्वारा अनुशंषित न्यूनतम वेतन प्रदान किया जाये।
10. स्नातक महाविद्यालयों के पात्र शिक्षकों को शोध-निदेशक के रूप में पंजीकृत करने की व्यवस्था की जाये।
11. शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को यू.जी.सी. वेतनमान प्रदान किये जायें।
12. निदेशक के पद पर वरिष्ठ शिक्षाविद् की ही नियुक्ति की जाये।
13. विश्वविद्यालयों के सिण्डीकेट आदि निकायों में महाविद्यालय-शिक्षकों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाये।
14. स्वायत्तशासी महाविद्यालय बनाने से पूर्व, उस महाविद्यालय के शिक्षकों व विद्यार्थियों को विश्वास में लिया जाये तथा आवश्यक सुविधाएँ पूर्व में ही सुनिश्चित की जायें।

प्रस्ताव क्रं. 3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति समग्र चिन्तन पर आधारित हो।

स्वतंत्रता के 65 वर्ष बीत जाने पर भी हम राष्ट्र के समक्ष एक सुस्पष्ट राष्ट्रीय शिक्षा-नीति प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। परिणामस्वरूप आज युवा शक्ति से भरपूर यह राष्ट्र विमुक्ति, शील एवं साधना की भावना से विमुख हो रहा है। युवा-शक्ति में सृजनात्मकता, शोध-वृत्ति एवं नवाचार के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो-इसलिए राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) की साधारण सभा शिक्षा-नीति के संबंध में निम्न प्रस्ताव पारित करती है -

1. प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा के लिए अलग-अलग नीति बनाने के स्थान पर एक समग्र शिक्षा-नीति तैयार किए जाने की आवश्यकता है।
2. शिक्षा आत्म-गौरव व राष्ट्र-गौरव का भाव उत्पन्न करे तथा शिक्षा का उद्देश्य चरित्र-निर्माण हो। शिक्षा शारीरिक, बौद्धिक व आध्यात्मिक उन्नयन का माध्यम होनी चाहिए।
3. परिवर्तनपरक तकनीक और सतत चली आ रही देश की सांस्कृतिक परम्परा में एक सुन्दर समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है।
4. शिक्षा-नीति में शिक्षा के स्वायत्तीकरण का प्रावधान हो, जिसके अन्तर्गत शिक्षा-व्यवस्था में सुधार एवं उत्कृष्ट शिक्षा हेतु नियमों का निर्माण शिक्षाविद ही करें। शिक्षा-नीति की क्रियान्वयन-प्रक्रिया, प्रबंधन तथा शिक्षा व्यवस्था का प्रशासन भी शिक्षाविदों द्वारा ही किया जाना चाहिए।
5. शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। अन्य विदेशी भाषाओं में दक्षता प्राप्त करने की व्यवस्था हो।
6. महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में उचित रोजगार के साथ मेल खाते विद्यार्थी-स्थानों के अनुसार ही प्रवेश हों। उच्च-स्तर पर क्षेत्रीय परिस्थिति के अनुरूप विद्यार्थी में जिस कौशल का विकास हो, उसके अनुसार कुछ घण्टे कमाने की स्वतंत्रता भी उसे नियमित अध्ययन के साथ दी जानी चाहिए।
7. शिक्षा के सभी स्तरों पर महिला एवं पुरुषों का लिंगानुपात उपयुक्त होना चाहिए। इसके लिए बालिकाओं के अध्ययन को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। गिरिजन-वनवासी महिलाओं के लिए उचित छात्रावासों की व्यवस्था होनी चाहिए।
8. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा में व्याप्त असमानताओं को ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा-सुविधाओं का विस्तार करके दूर किया जाना चाहिए।

शोक प्रस्ताव

रुक्टा (राष्ट्रीय) के गत अधिवेशन के पश्चात् शिक्षा जगत के हमारे कुछ साथी प्रभुतत्व में लीन हो गए हैं। संगठन के 54वें अधिवेशन की यह साधारण सभा प्रो. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, प्रो. ललित किशोर चतुर्वेदी (जयपुर), प्रो. कमल किशोर मीणा (सवाई माधोपुर), प्रो. एन. बी. सक्सेना (बीकानेर), प्रो. के.बी.एस. ढिल्लो (श्रीगंगानगर), प्रो. आशा जगदीश (अजमेर), प्रो. रामरतन गोयल (अलवर), प्रो. पी.एन. अग्रवाल (सवाईमाधोपुर), प्रो. एच. एल. भादु (सूरतगढ़), प्रो. ए.बी. किलेदार (भरतपुर), प्रो. आर. एस. नेगी (बीकानेर) और प्रो. एस. पी. माथुर (अजमेर) के निधन से शिक्षा-जगत में हुई अपूरणीय क्षति के लिए गहन शोक प्रकट करती है एवं ईश्वर से प्रार्थना करती है कि उनकी आत्मा को शान्ति एवं उनके परिजनों को इस असह्य दु:ख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

आय-व्यय खाता

31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

व्यय	राशि (रु.)	आय	राशि (रु.)
इकाइयों को सहायता	1,00,500.00	सदस्यता 2014-2015	4,02,000.00
डाक व्यय	22,874.00	इकाइयों से विशेष सहायता	29,210.00
दूरभाष व मोबाईल	20,986.00	इकाइयों का अंश	1,00,500.00
प्रिंटिंग व स्टेशनरी	62,321.00	आजीवन सदस्यता	7000.00
यात्रा व्यय	1,11,826.00	बचत खाते पर ब्याज	14,653.00
पारिश्रमिक	14,400.00	मियादी जमा खाते पर ब्याज	67,357.00
शैक्षिक महासंघ संबद्धता शु.	5,025.00	बांसवाड़ा रुक्टा राष्ट्रीय	66,000.00
विविध व्यय	12,390.00	अधिवेशन खाता	
बैंक चार्जेज	212.00	राष्ट्रीय परिसंवाद उच्च शिक्षा का	4,622.00
योग	**3,50,534.00**	आधिक्य	
आय का व्यय पर आधिक्य	3,40,808.00		
कुल योग	**6,91,342.00**	**योग**	**6,91,342=00**

चिट्ठा 31 मार्च, 2015

दायित्व	राशि (रु.)	सम्पत्तियाँ	राशि (रु.)
आय का व्यय पर आधिक्य -			
गत वर्षों का आधिक्य	2653334.00	**रोकड़ बचत बैंक खाता**	
इस वर्ष का आधिक्य	340808.00	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक	5976.00
कुल आधिक्य	**2994142.00**	यूको बैंक	513721.00
महामंत्री को देने बाकी	73146.00	**योग**	**519697.00**
		मियादी जमा खाता	
		आई.सी.आई.सी.आई. बैंक	1105331.00
		यूको बैंक	1442260.00
		योग	**2547591.00**
योग	**3067288.00**	**कुल योग**	**3067288.00**

ह.
डॉ. दिग्विजयसिंह शेखावत
अध्यक्ष

ह.
डॉ. नारायण लाल गुप्ता
महामंत्री

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने रुक्टा (राष्ट्रीय) के 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की लेखा पुस्तकें, आय एवं व्यय खाता और चिट्ठे का अंकेक्षण किया है और मैं प्रतिवेदित करता हूँ कि मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारे अंकेक्षण उद्देश्य हेतु आवश्यक समस्त सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण मैंने प्राप्त कर लिये हैं। मेरी राय में और मेरी जानकारी के अनुसार तथा मुझे जो सूचनाएँ और स्पष्टीकरण दिये गए हैं, वे संगठन की स्थिति, विवरण (चिट्ठा) का 31 मार्च 2015 को सही और प्रमाणित स्थिति प्रकट कर रहा है और इस तिथि को आय का व्यय पर आधिक्य भी प्रकट हो रहा है।

ह.
(डॉ. सोमकान्त भोजक)
अंकेक्षक